विविध सिविल

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन के समक्ष

किरण कुमार पुरी, - याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब: विश्वविद्यालय और अन्य, - उत्तरदाता

1969 की सिविल रिट संख्या 173

7 अप्रैल, 1969

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1967, खंड I भाग III -विनियम 20- के तहत कार्रवाई- क्या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जो घटना के दिन परीक्षार्थी नहीं है लेकिन परीक्षा में परीक्षार्थी है।

पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, *1967* के विनियम *20* के अनुसार, खंड I, भाग III में प्रावधान है कि एक उम्मीदवार जो परीक्षा अधीक्षक या पर्यवेक्षी स्टाफ के किसी अन्य सदस्य की बात मानने से इनकार करता है या किसी अन्य उम्मीदवार के साथ अपनी सीट बदलता है या जानबूझकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर किसी अन्य उम्मीदवार का रोल नंबर लिखता है, या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करता है, या अन्यथा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार करता है, अधीक्षक द्वारा निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा। अधीक्षक या पर्यवेक्षी स्टाफ के किसी सदस्य की आज्ञा का पालन करने या किसी अन्य उम्मीदवार के साथ सीट बदलने, या किसी अन्य उम्मीदवार के रोल नंबर को लिखने या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने, या परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार करने का सवाल, जब "अधीक्षक द्वारा निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा" शब्दों के साथ पढ़ा जाता है, तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है कि संबंधित व्यक्ति को उस विशेष दिन एक परीक्षार्थी होना चाहिए और परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं। निष्कासन की शक्ति का प्रयोग अधीक्षक द्वारा केवल उस उम्मीदवार के संबंध में किया जा सकता है जो परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा हॉल में मौजूद है। "या अन्यथा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार करता है" शब्दों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसे बाकी नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो एकमात्र अपरिवर्तनीय निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि विनियमन **20** केवल उस व्यक्ति पर लागू होता है जो किसी विशेष पेपर में उपस्थित होने वाला उम्मीदवार है और परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं है। **(**पैरा **6)**

भारत के संविधान के अनुच्छेद ***226*** और ***227*** के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सर्टिओरारी, मंडामस, कुओ वारंटों या किसी भी रिट, निर्देश या आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें **30** अक्टूबर, **1968** के स्थायी समिति के आदेश को रद्द कर दिया जाए, जिसमें याचिकाकर्ता को दो साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया था और यह भी प्रार्थना की गई थी कि विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील शील कुमार सांवलका।

नरिंदर सिंह और आर.एस. मोंगिया उत्तरदाताओं के लिए वकील ।

निर्णय

न्यायमूर्ति, जैन - किरण कुमार पुरी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता को पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के विनियमन 20 के तहत दो साल की अवधि यानी 1968 और 1969 (चार सत्र) के लिए अयोग्य घोषित करने के स्थायी समिति के आदेश को रद्द करने के लिए एक रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है। 1967, खंड I, पृष्ठ 111, दिनांक 30 अक्तूबर, 1968 (अनुलग्नक 'सी')।

(2) आरोप है कि याचिकाकर्ता कपूरथला के रणधीर कॉलेज में अप्रैल, 1968 में आयोजित बीए पार्ट वन परीक्षा का उम्मीदवार था और उसका रोल नंबर 4026 था। वह 9 मई, 1968 को गणित पेपर 'बी' की परीक्षा में उपस्थित हुए, और रसायन विज्ञान 'बी' के लिए उनकी अगली परीक्षा 18 मई, 1968 को होनी थी।

(3) 15 मई, 1968 को कुछ छात्र सुबह 11.30 बजे परीक्षा हॉल के बाहर इकट्ठा हुए और नारे लगाए और परीक्षा हॉल पर पत्थर फेंके। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन छात्रों को हटा दिया। 16 मई, 1968 को परीक्षा केंद्र के अधीक्षक श्री एस डी चक्रवर्ती द्वारा विश्वविद्यालय को घटना की एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें घटना का विवरण दिया गया था और प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों में से एक के रूप में अकेले याचिकाकर्ता का नाम लिया गया था। याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय ने एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए तलब किया था जिसमें उसने दलील दी थी कि उसका कथित प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है और वह चंडीगढ़ से बाहर है। उनके बयान के समर्थन में दो गवाहों सर्वश्री, जे. आर. वर्मा और दीप खुल्लर से बचाव में पूछताछ की गई और स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व सहायक निदेशक डॉ. नरिंजन सिंह, एमबी, बीएस (अब चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में निजी मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे) से बीमारी का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया। याचिकाकर्ता के साक्ष्य के बंद होने के बाद, स्थायी समिति ने अधीक्षक का बयान दर्ज किया और उसके बाद याचिकाकर्ता को पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1967 के खंड 1 के विनियमन 20 के तहत दो साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। स्थायी समिति के इस आदेश को अनुलग्नक ग में इस याचिका के माध्यम से अवैध, अमान्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई है।

(4) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार श्री सुजान सिंह द्वारा दायर रिटर्न में याचिका में लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया है। परीक्षा केंद्र पर अधीक्षक रहे श्री सहदेव चक्रवर्ती ने भी याचिका में लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हुए एक हलफनामा दायर किया है।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सांवलका ने दलील दी कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1967 (खंड एक) का नियम 20 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और इस नियमन के तहत याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराना गैरकानूनी है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील एमएल नरिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि विनियमन 20 पूरी तरह से लागू था और याचिकाकर्ता को इस विनियमन के तहत सही रूप से अयोग्य ठहराया गया था।

(6) पक्षकारों के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों पर विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील अच्छी तरह से स्थापित है। विनियम 20 निम्नलिखित शब्दों में है -

> " 20. एक उम्मीदवार जो परीक्षा अधीक्षक या पर्यवेक्षी स्टाफ के किसी अन्य सदस्य का पालन करने से इनकार करता है या किसी अन्य उम्मीदवार के साथ अपनी सीट बदलता है या जानबूझकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर किसी अन्य उम्मीदवार का रोल नंबर लिखता है या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करता है, या अन्यथा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार करता है, अधीक्षक द्वारा निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा, और अपराध की गंभीरता के अनुसार निम्नलिखित में से कोई भी सजा दी जाएगी: –
>
> 1. संबंधित पेपर की उत्तर-पुस्तिका को रद्द करना;
> 2. किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित किया जाता है जो तीन साल तक बढ़ सकता है।

यह नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास उस दिन कोई पेपर नहीं था जिस दिन अशांति हुई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील पर निर्णय के लिए जो सवाल आता है, वह यह है कि क्या विनियमन 20 उस व्यक्ति पर लागू होता है जो परीक्षा में एक उम्मीदवार है या केवल एक उम्मीदवार पर जिसे किसी विशेष दिन पेपर मिला है।

इस विनियमन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक उम्मीदवार जो परीक्षा अधीक्षक या पर्यवेक्षी स्टाफ के किसी अन्य सदस्य की बात मानने से इनकार करता है या किसी अन्य उम्मीदवार के साथ अपनी सीट बदलता है या जानबूझकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर किसी अन्य उम्मीदवार का रोल नंबर लिखता है, या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करता है, या अन्यथा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार करता है, अधीक्षक द्वारा निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा। अधीक्षक या पर्यवेक्षी स्टाफ के किसी सदस्य की आज्ञा का पालन करने या किसी अन्य उम्मीदवार के साथ सीट बदलने, या किसी अन्य उम्मीदवार के रोल नंबर को लिखने या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने, या परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार करने का सवाल, जब "अधीक्षक द्वारा निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा" शब्दों के साथ पढ़ा जाता है, तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है और वह यह है कि संबंधित व्यक्ति को परीक्षार्थी होना चाहिए। उस विशेष दिन और परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार नहीं। अधीक्षक द्वारा निष्कासन के अलावा, अपराध की गंभीरता के आधार पर दो अन्य दंड प्रदान किए जाते हैं, वह यह है कि उस विशेष पेपर की उसकी उत्तर-पुस्तिका रद्द कर दी जाए या उसे तीन साल तक की किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। निष्कासन की शक्ति का प्रयोग अधीक्षक द्वारा केवल एक उम्मीदवार के संबंध में किया जाता है जो एक परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा हॉल में मौजूद है। इसलिए किसी विशेष पेपर को रद्द करने का सवाल उस उम्मीदवार के संबंध में भी उठ सकता है जो किसी विशेष पेपर में उपस्थित हो रहा है। विश्वविद्यालय को एक और शक्ति दी जाती है कि वह किसी व्यक्ति को तीन साल तक की किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है यदि वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि उम्मीदवार का दुर्व्यवहार गंभीर और गंभीर प्रकृति का था। प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा 'परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार करना' शब्दों पर बहुत जोर दिया गया था और यह तर्क दिया गया था कि इन शब्दों से एकमात्र निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि विनियमन 20 एक ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार था और इसका आवेदन केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं था जो किसी विशेष दिन परीक्षार्थी था। मुझे डर है कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि इन शब्दों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाकी विनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो एकमात्र अनूठा निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि विनियमन 20 केवल उस व्यक्ति पर लागू होता है जो किसी विशेष पेपर में उपस्थित होने वाला उम्मीदवार है और परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं है।

(7) 'अनुचित साधनों का उपयोग' शीर्षक के तहत कुछ अन्य विनियमों का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसके तहत यह विनियम 20 आता है, जो मेरे द्वारा लिए जा रहे दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। विनियमन 10 अधीक्षक या उपाधीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन करता है जो उन्हें परीक्षा शुरू होने से पहले करना होता है। विनियम 11 के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों में, जब संदेह या पता चलता है, तो रजिस्ट्रार को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। इस विनियम के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग का पता चलने के बाद किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है। विनियम 12, 13 और 14 में अनुचित साधनों के उपयोग की विभिन्न स्थितियों में अलग-अलग प्रक्रिया एं भी निर्धारित की गई हैं। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अपनी दलील के समर्थन में एक भी विनियमन या अन्य प्रासंगिक प्रावधान का उल्लेख नहीं किया। इस मामले के इस दृष्टिकोण में मैं मानता हूं कि विनियमन 20 का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं है और इस विनियमन के तहत याचिकाकर्ता की अयोग्यता अवैध, अनुचित और टिकाऊ नहीं है।

(8) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की पहली दलील पर विचार किया है, मैं विद्वान वकील की शेष दलीलों से निपटने का प्रस्ताव नहीं करता हूं।

(9) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और स्थायी समिति के उस आदेश को रद्द करता हूं जिसमें याचिकाकर्ता को पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1967 (खंड 1) के विनियम 20 के तहत दो साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। मामले की परिस्थितियों में शुल्क के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के समिति उपयोग कि लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा